सुविचार

लालच वह अवगुण होता है, जो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है। जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता है।

दैनिक
पंचकूला ऑब्जर्वर
सच के साथ, समाज के साथ

वर्ष : 1 | अंक : 56 | पंचकूला। वीरवार, 2 अप्रैल 2026 | www.panchkulaobserver.com | मूल्य : 3 रुपए | RNI No. : HRBIL/25/4317 | पृष्ठ : 4

एक नजर

रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाने पर फार्मासिस्टों का नाम काट देगी फार्मेसी काउंसिल

पंचकूला. हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल ने राज्य के फार्मासिस्टों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए 3 महीने की ग्रेस पीरियड देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन सभी फार्मासिस्टों के लिए लागू होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 या उससे पहले समाप्त हो चुका है। काउंसिल के चेयरमैन बीबी सिंगल ने बताया कि राज्य में करीब 70 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 10 हजार फार्मासिस्टों, जिनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था, उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है। यह निर्णय काउंसिल की कार्यकारणी की बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी फार्मासिस्टों को 30 जून तक अपना नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर संबंधित फार्मासिस्ट का नाम फार्मासिस्ट रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। काउंसिल के अनुसार 1 जुलाई से नवीनीकरण में देरी करने वालों पर प्रति वर्ष 500 रुपये का लेट फीस लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। साथ ही नए नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बीबी सिंगल ने बताया कि कार्यकारणी में यह फैसला लिया गया कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, तो उनका नाम रजिस्टर से भविष्य में काट दिया जाएगा। यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा। एक बार रजिस्टर से नाम कटने के बाद फार्मासिस्ट को अपना नाम रिस्टोरेशन के लिए आवेदन करते हुए नवीनीकरण ना करवाने का कारण भी बताना होगा। उसके बाद उसके आवेदन को तथ्यों सहित काउंसिल की कार्यकारणी के पास रखा जाएगा और कार्यकारणी को तथ्य सही लगे, तभी उसका रजिस्ट्रेशन बहाल किया जाएगा। बीबी सिंगल ने सभी फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाकर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

चुनाव आयोग ने असम-केरल-पुडुचेरी के लिए 282 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। चुनाव आयोग के मुताबिक, इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 282 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इनमें असम के लिए 136, केरल के लिए 108 और पुडुचेरी के लिए 38 पर्यवेक्षक शामिल हैं। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि चुनाव उत्सवी माहौल में, निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न होने चाहिए। किसी भी प्रकार की धमकी, हिंसा या प्रलोभन को सख्ती से रोका जाए। आयोग ने पर्यवेक्षकों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर पर्यवेक्षकों के संपर्क नंबर और शिकायत सुनवाई का समय प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

जीएसटी संग्रह मार्च में 8.8 प्रतिशत बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार

नई दिल्ली. सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2026 में सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह घरेलू अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और आयात से जुड़े जीएसटी संग्रह में तेज वृद्धि होना है। यह जानकारी सरकार द्वारा बुधवार को दी गई। मार्च में सकल जीएसटी आय 2,00,064 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 1,83,845 करोड़ रुपए थी। इस बढ़ोतरी की वजह आयात पर लगने वाले जीएसटी में 17.8 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी है। हालांकि, घरेलू सामान पर लगने वाला जीएसटी में सालाना आधार पर 5.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अगर 22,074 करोड़ रुपए के रिफंड को हटा दिया जाए तो मार्च में शुद्ध जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 1,77,990 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सकल जीएसटी संग्रह 8.3 प्रतिशत बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में यह 20.55 लाख करोड़ रुपए था। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह (रिफंड को हटाकर) 19.34 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है। इस बीच, उपकर संग्रह में महीने के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई और यह (-177) करोड़ रुपए पर नकारात्मक हो गया, जिसका मुख्य कारण अधिक रिफंड और समायोजन थे।

नाटो से अलग हो सकता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बोले- ये कागजी शेर

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे NATO से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने NATO को कागजी शेर बताया। एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा कि वे पहले से ही NATO से ज्यादा प्रभावित नहीं थे और उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही मानते हैं। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने साथियों के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इस बार कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया। उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अमेरिका ने मदद की थी, लेकिन अब वही समर्थन अमेरिका को नहीं मिल रहा। यह बयान तब आया है जब NATO देशों ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि NATO देश होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अपने वॉरशिप भेजें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि यह इजराइल का आखिरी युद्ध हो।

कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान व सुरक्षा से खिलवाड़ किया : पीएम मोदी

चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पंचकूला ऑब्जर्वर

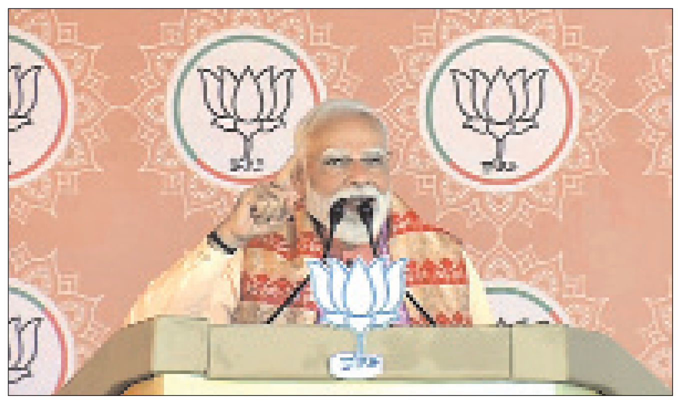

बिस्वनाथ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिस्वनाथ जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम असम में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और यह अटूट विश्वास %डबल इंजन सरकार% द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा की आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम की पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्यधारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस ने यहां अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी होती अपनी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई।

उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस, विकास विरोधी है। कांग्रेस, आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किये हैं, जो सिर्फ असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है।

कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप अवैध घुसपैठियों को मुख्यधारा में लाना था। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जमीन पर अवैध कब्जे की अनुमति दी, ताकि वे सत्ता में बने रह सकें। आज, भाजपा जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के कुशासन ने असम के जंगलों, अभयारण्यों और एक सींग वाले गैंडों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा-एनडीए को पूरे देश में समर्थन इसलिए भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वहीं, कांग्रेस को देश की विरासत से...देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। असम की जनता भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का अपमान भी नहीं भूल सकती।

भाजपा-एनडीए सरकार ने महान भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने इसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। हमने तो कांग्रेस के भी उन नेताओं का सम्मान किया, जिन्होंने असम और देश के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन, कांग्रेस अपने नेताओं को भी भुला देती है।

विकसित असम के निर्माण में नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों को भी फायदा होता है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे-बेटियों के लिए रोजगार के अवसर बनते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक, जब कोई असम आता था, तो यहां की बदहाली को देखकर हैरान हो जाता था। लेकिन, आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं, एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ समय पहले दुनिया ने असम के वो हाइवे भी देखा है, जहां लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गाड़ियां भी गुजरेंगी। सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अपनी पहली पानी के अंदर बनी दो-ट्यूब वाली सड़क और रेल सुरंग बना रही है, जिस पर 18,662 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर धमाका

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सेक्टर-३७ स्थित बीजेपी के पंजाब मुख्यालय के बाहर बुधवार शाम करीब 5 बजे धमाका हुआ। जिसके चलते शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आनन-फानन में धमाके की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही यूटी पुलिस के आईजी पुष्पेंद्र कुमार, एसएसपी कंवरदीप कौर और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचेऔर मामले की जांच में जुट गए है। जानकारी के अनुसार, सेक्टर-37 स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर बुधवार शाम 5 बजे एक्टिवा स्कूटर के पास जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक्टिवा स्कूटर और कार को नुकसान पहुंचा। धमाके की इतनी जोरदार आवाज थी कि बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए। जिस एक्टिवा स्कूटर के पास विस्फोट किया गया वह एक्टिवा नयागांव निवासी हर्ष का था। हर्ष ने बताया कि वह 4 साल से सेक्टर 37 स्टेट बीजेपी कार्यालय में कॉल सेंटर पर काम करता है। जिसकी ड्यूटी सुबह 9.00 बजे से शान 6 बजे तक होती है। हर रोज की तरह उसने बुधवार को भी अपना एक्टिवा पार्किंग में सुबह खड़ा किया था, लेकिन शाम 5 बजे कार्यालय के अंदर बैठे हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जब हम बाहर आए तो धुआं धुआं हो गया था।

फल उत्पादन, प्राकृतिक खेती और क्लस्टर आधारित मॉडल से बढ़ेगी किसानों की आय : नायब

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फल फसलों के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्लस्टर आधारित खेती मॉडल विकसित किया जाए, ताकि किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट जैसी प्रमुख फल फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर क्लस्टर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन फलों की बाजार में मांग और लाभकारी मूल्य को देखते हुए किसानों को इनके उत्पादन, पौध उपलब्धता, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, दलहन, फल फसलों तथा गन्ने के ऊतक संवर्धन आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि हर जिले की कृषि और बागवानी क्षमता का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को बहु-फसली, बहु-उत्पाद और उच्च मूल्य आधारित खेती से जोड़कर स्थायी आय के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में विकसित सफल संकर किस्मों, फल पौधों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाए, ताकि प्रदेश के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली पौध और बीज उपलब्ध हो सकें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 1,40,000 एकड़ सेम एवं लवणीय भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जैव निकास के तहत सफेदा (यूकेलिप्टस) के पेड़ किसानों के खेतों की मेड़ों, नहरों के किनारों तथा नालों की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर लगाए जाएं, ताकि जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक रूप से कम किया जा सके। सफेदा के पेड़ अपनी गहरी जड़ों और अधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण सेम प्रभावित भूमि के सुधार में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर चिन्हित किए जाएं। इन क्लस्टरों में किसानों को जीवामृत, जैविक घोल, ड्रम और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए।

उन्होंने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत द्वारा अपनाई जा रही प्राकृतिक खेती पद्धति को आधार बनाकर इसे लागू किया जाए।

कीटनाशक जांच और अत्याधुनिक जैविक प्रयोगशाला

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रयोगशालाओं में फसलों, फल-सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों में कीटनाशक दवाइयों और कीटनाशक अवशेषों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।जिन रसायनों का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जिनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ती है, उनके उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। नमूनों की जांच के लिए नमूने नियमित रूप से प्रयोगशाला भेजे जाएं तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एक अत्याधुनिक जैविक प्रयोगशाला स्थापित की जाए, जिसमें जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन से संबंधित सभी नमूनों की नियमित जांच की जा सके। इस प्रयोगशाला में मिट्टी, पानी, जैविक खाद, फसल और अन्य आवश्यक घटकों के नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जैविक खेती की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकों की प्रभावी निगरानी हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र बढ़खालसा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

फर्जी डीएसपी बनकर 35 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 2 सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस ने फर्जी वर्दी व नकदी बरामद की

सीसीटीवी टेंडर दिलवाने के बहाने किया फ्रॉड, दोनों को रिमांड खत्म होने के बाद भेजा जेल

पंचकूला ऑब्जर्वर

पंचकूला. पंचकूला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने एक बडी सफलता हासिल करते हुए हरियाणा पुलिस का फर्जी डीएसपी बनकर और टेंडर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधडी के मामले में मुख्य आरोपी विपुल गोयल और उसके भाई तरुण गोयल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फ्रॉड की कुछ राशि और हरियाणा पुलिस के डीएसपी की फर्जी वर्दी बरामद की है। एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि हमें पानीपत निवासी योगेश नामक व्यक्ति से एक शिकायत मिली थी। जिसके अनुसार वर्ष 2014 में तरुण गोयल ने अपने भाई विपुल गोयल की मुलाकात योगेश से करवाई और दावा किया कि विपुल ने डीएसपी का पद हासिल कर लिया है। विश्वास जीतने के लिए आरोपी विपुल अक्सर पुलिस की वर्दी पहनकर योगेश से मिलता था। आरोपियों ने योगेश को सीसीटीवी कैमरे लगाने का सरकारी टेंडर दिलाने का लालच दिया। विश्वास में आकर पीडित ने फरवरी 2017 में पंचकूला सेक्टर-6 में आरोपियों को 15 लाख रुपये नकद सौंपे। इसके बाद विभिन्न बैंक खातों और नकद माध्यमों से किश्तों में कुल 35 लाख रुपये ऐंठ लिए गए।

पीडित ने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक टेंडर न मिलने पर जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो दोनों भाई उसे टालते रहे। जून 2023 में दबाव बनाने पर आरोपियों ने केवल 1.96 लाख रुपये वापस किए और उसके बाद संपर्क तोड दिया। जांच करने पर पीडित को पता चला कि विपुल गोयल पुलिस में कोई अधिकारी नहीं है।

डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता शिकायत के आधार पर 11 सितंबर 2025 को सैक्टर-7 थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 406, 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर योगविन्द्र सिंह के नेतृत्व में जांच अधिकारी एएसआई गुरबचन ने टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 28 मार्च गिरफ्तार किया। 29 मार्च को कोर्ट से 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी तरुण और विपुल से धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की गई हरियाणा पुलिस की डीएसपी की फर्जी वर्दी बरामद की गई। आज रिमांड समाप्त होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।

सेक्टर-10 की समस्याओं को होवा का हल्ला बोल, कमिश्नर ने दिया समाधान का आश्वासन

सेक्टर-10 में सफाई बदहाल, खुले गड्ढों पर सख्त हुए निगम कमिश्नर विनय कुमार

पंचकूला ऑब्जर्वर

पंचकूला। नगर निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने सोमवार को सेक्टर-10 का निरीक्षण किया। इस दौरान हाउस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (होवा) के पदाधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। एसोसिएशन के चेयरमैन भारत हितैषी, संस्थापक एन.सी. स्वामी, मुख्य संरक्षक एस.के. शर्मा, प्रधान बी.एम. कौशिक, संरक्षक बाबू दलजीत सिंह, संरक्षक एवं समाजसेवी संजय आहूजा, वरिष्ठ उपप्रधान सुभाष शर्मा, संगठन मंत्री इकबाल भसीन मार्गदर्शक वी एस मनियम सहित अन्य पदाधिकारियों ने कमिश्नर को बताया कि एयरटेल की ओर से अंडरग्राउंड फाइबर केबल बिछाने के दौरान खोदे गए गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है। टेंडर नियमों के अनुसार इन्हें भरकर सीमेंट-बजरी से पक्का किया जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते कई लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं।

शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मौके पर मौजूद एक्सियन प्रमोद कुमार को निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार से गड्ढों को तुरंत भरवाकर पक्का कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर ठेकेदार के अन्य कार्य रोक दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा एसोसिएशन ने सेक्टर-10 में सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। पदाधिकारियों ने बताया कि गलियों और सड़कों पर नियमित झाड़ू नहीं लगती और हार्टिकल्चर वेस्ट महीनों तक नहीं उठाया जाता। कमिश्नर ने विभिन्न स्थानों पर बंद पड़ी गलियों और ब्लॉक सड़कों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एसोसिएशन ने मकान नंबर 424 के साथ लगती सरकारी ग्रीन लैंड को पब्लिक पार्क के रूप में विकसित करने की मांग भी उठाई, जिस पर कमिश्नर ने जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारत हितैषी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। संरक्षक संजय आहूजा ने भी काफी समस्याओं को उजागर किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।

एक नजर

चब्बेवाल में फलों-सब्जियों की बड़ी एग्रो इंडस्ट्री लगेगी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिले सांसद राजकुमार चब्बेवाल

नई दिल्ली. पंजाब के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र में फलों और सब्जियों से संबंधित एक बड़ी एग्रो इंडस्ट्री स्थापित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में सांसद राजकुमार चब्बेवाल ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर परियोजना पर विस्तृत चर्चा की थी। बैठक के बाद केंद्र स्तर पर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि यह अत्याधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट अगले 12 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी। इस इंडस्ट्री के स्थापित होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार ने भी इस परियोजना को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यूनिट के शुरू होने से कंडी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में फलों और सब्जियों की खेती को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, यह प्रोजेक्ट मटर और आलू जैसी प्रमुख फसलों की प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

युद्ध नशेयां विरुद्ध के 13 महीने: 2458 किलो हेरोइन सहित 56 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई नशों के खिलाफ निर्णायक मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' के 13 महीने पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 39,760 एफआईआर दर्ज करते हुए 56,372 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों से 2458 किलो हेरोइन भी बरामद की है। इस मुहिम की शुरुआत के बाद, पंजाब पुलिस द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों के तहत राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक ही समय पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 2458 किलो हेरोइन के अलावा पुलिस ने 724 किलो अफीम, 345 क्विंटल भुक्की, 69 किलो चरस, 843 किलो गांजा, 37 किलो आईसीई, 51 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 17.28 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है। पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ इस अभियान के 396वें दिन 86 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 269 ग्राम हेरोइन, 1000 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही केवल 396 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल तस्करों की संख्या 56,458 हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि नशा छुड़ाओ अभियान के तहत आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए उपचार लेने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीमों ने लगातार 71वें दिन 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान जारी रखते हुए 483 छापेमारी के बाद 184 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 87 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई और पांच भगोड़े अपराधियों (पी.ओ.) को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी सूचना साझा कर सकते हैं।

जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया जा रहा 1,100 करोड़ का निवेश, पंजाब के औद्योगिक विकास और ग्रीन ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा : अरोड़ा

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़ पंजाब के उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा 1,100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रणनीतिक विस्तार की योजना की घोषणा की गई है, जिससे पंजाब के औद्योगिक विकास और ग्रीन ऊर्जा के उपयोग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, 'जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।' उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, 'इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।' इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, 'आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।'

निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है पंजाब

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा। भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, 'आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।'

मोदी के बराबर पहुंचे मूसेवाला के सब्सक्राइबर, 3 करोड़ फैंस वाला पहला पंजाबी सिंगर बना सिद्धू

चंडीगढ़. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिवंगत सितारे सिद्धू मूसेवाला का क्रेज उनके निधन के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल ने 3 करोड़ (30 मिलियन) सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वह 3 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ इंडिया के पहले सिंगर बन गए हैं। इस बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला ने यह मुकाम महज 125 वीडियो के साथ हासिल किया, जबकि नरेंद्र मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर करीब 3.01 करोड़ सब्सक्राइबर 34 हजार से अधिक वीडियो के साथ हैं। इस लिहाज से मूसेवाला की लोकप्रियता और फैन एंगेजमेंट को बेहद खास माना जा रहा है। 29 मई 2022 को हत्या के समय सिद्धू मूसेवाला के चैनल पर करीब 1 करोड़ सब्सक्राइबर थे। इसके बाद फैंस की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ और एक साल में यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया। अब अप्रैल 2026 तक चैनल 3 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा छू चुका है, जबकि कुल व्यूज 9.8 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं।

बलतेज पन्नू और हरपाल जुनेजा द्वारा पीआरटीसी कर्मचारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत

पटियाला. आम आदमी पार्टी के राज्य महासचिव एवं मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू और पीआरटीसी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल जुनेजा द्वारा पीआरटीसी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह योजना एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली और बलविंदर सिंह झाड़वां (वाइस चेयरमैन) भी उपस्थित थे।

बलतेज पन्नू ने बताया कि पीआरटीसी को एक परिवार मानते हुए, कर्मचारियों—चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त—के लिए दो दिवसीय विशेष कैंप लगाया गया है। यह कैंप चेयरमैन हरपाल जुनेजा के सहयोग से आयोजित किया गया है और अगले दिन भी जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। यह इलाज पूरी तरह मुफ्त है और इसमें सभी टेस्ट भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 900 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 30 लाख लोग अपने हेल्थ कार्ड बनवा चुके हैं। योजना के कार्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही और लोग इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का ऐसा मॉडल राज्य बन गया है जहां लोगों को कैशलेस और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विदेश जाते थे, लेकिन अब ये सुविधाएं पंजाब में ही उपलब्ध हैं। सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक से लेकर सरकारी अस्पतालों तक स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। एडवोकेट हरपाल जुनेजा ने कहा कि यह हेल्थ कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। उन्होंने कहा कि यह योजना लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। अब तक 30 लाख से अधिक कार्ड तैयार हो चुके हैं, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में 65 लाख परिवारों के हेल्थ कार्ड तैयार हो जाएंगे। इस योजना के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है, केवल पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना आवश्यक है। इस मौके पर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल (मैनेजिंग डायरेक्टर), नवदीप कुमार (अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर), मनिंदरपाल सिंह सिद्धू (जीएम), जतिंदरपाल सिंह ग्रेवाल (कार्यकारी इंजीनियर), अमनवीर सिंह टिवाना (जीएम), विक्की घनौर, गुरविंदर शंटी, रविंदर पाल सिंह, प्रिंस लांबा, वीरपाल कौर, महिंदर मोहन सिंह, संदीप बंधू, गज्जन सिंह, जसविंदर सिंह रिम्पा, राहुल महिता, सिमरन ग्रेवाल, मोंटी ग्रोवर, नवनीत राजबीर सिंह चहल, सुशील, अमित विक्की, ऋषव राजपूत और शुभम भटनागर सहित अन्य उपस्थित रहे।

लंबित आरसी व ड्राईविंग लाइसेंसों के आवेदनों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश: चीमा

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़. पंजाब के वित्त, परिवहन, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) जारी करने से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए आज यहां परिवहन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में परिवहन सचिव वरुण रूजम, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परनीत शेरगिल, सचिव आर.टी.ए., आर.टी.ओ. और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य ध्यान आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित समस्याओं के समाधान पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सत्यापन और अनुमोदन स्तर पर लंबित सभी आवेदनों का सख्त संज्ञान लिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी वाले सभी मामलों की बारीकी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा लंबित आवेदनों के साथ-साथ देरी के कारणों का विस्तृत डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि फेसलेस और संपर्क रहित माध्यम से दी जा रही ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन श्रेणियों में लंबित आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

नागरिकों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत प्रिंटिंग शाखा में आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाएगा और इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा और परिवहन संचालन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईवे ट्रैफिक कैमरों की तैनाती और निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने परिवहन नेटवर्क की कुशलता भरोसेयोगिता और पहुंच को ओर अधिक यक़ीनी बनाने के लिए समय-सारिणी की समीक्षा कर और शेष रूटों को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवाओं को अधिक कुशल, विश्वसनीय और सुलभ बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

हलवारा हवाई अड्डा उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार; बुकिंग जल्द होगी शुरू, 15 मई से उड़ानें शुरू; कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पहली टिकटें की बुक

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़. पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हलवारा हवाई अड्डे से 15 मई, 2026 को उड़ानें शुरू हो जाएंगी और जल्द ही फ्लाइट बुकिंग भी शुरू होगी। शुरुआत में एयर इंडिया की दो उड़ानें लुधियाना को दिल्ली से जोड़ेंगी, जिससे 30 वर्षों का सपना साकार होगा। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने अपनी पत्नी के साथ 15 मई, 2026 को दिल्ली से हलवारा जाने वाली पहली फ्लाइट बुक करवाई है, जो इस ऐतिहासिक सफर में एक निजी और सार्वजनिक मील का पत्थर है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सेक्टर की टिकटें तेजी से बिक रही हैं।

उड़ानों की शुरुआत निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो संजीव अरोड़ा की क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने और पंजाब, विशेष रूप से लुधियाना और इसके आसपास के जिलों के आर्थिक विकास में तेजी लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को पुनर्जीवित करने और इसमें तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लुधियाना के निकट एक कार्यशील हवाई अड्डे का सपना साकार होगा। हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवासियों और व्यावसायिक समुदाय को निर्बाध यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे निर्यातकों, उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा, जिससे लुधियाना की स्थिति एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। संजीव अरोड़ा ने इस परियोजना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी भागीदारों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगपतियों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल बुनियादी ढांचे के विकास को ही नहीं दर्शाती, बल्कि पंजाब को राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक गलियारों से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानों की शुरुआत पंजाब की विकास गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिससे बेहतर संपर्क, अवसर और विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

पंजाब में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण : मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की 'शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल' श्रृंखला के हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का चार साल का व्यापक रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें यह दिखाया गया कि निरंतर नीतिगत हस्तक्षेप ने गांवों के बुनियादी ढांचे को कैसे बदला है, जमीनी स्तर पर प्रशासन को मजबूत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत 'आप' सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे। उन्होंने आगे कहा, पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।

उन्होंने कहा, 2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा, राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, 2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहा?ियों का रोजगार सृजित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा, नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर 'गांव के सरपरस्त' के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए। उन्होंने कहा, 117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए। उन्होंने कहा, समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है।

ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है। एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।

फल उत्पादन, प्राकृतिक खेती और क्लस्टर आधारित मॉडल से बढ़ेगी किसानों की आय: मुख्यमंत्री

सेम एवं लवणीय भूमि सुधार, जैव निकास और जैविक प्रयोगशाला पर विशेष जोर

पंचकूला ऑब्जर्वर

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फल फसलों के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्लस्टर आधारित खेती मॉडल विकसित किया जाए, ताकि किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट जैसी प्रमुख फल फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर क्लस्टर विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इन फलों की बाजार में मांग और लाभकारी मूल्य को देखते हुए किसानों को इनके उत्पादन, पौध उपलब्धता, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने अरहर,

सोयाबीन, मूंगफली, दलहन, फल फसलों तथा गन्ने के ऊतक संवर्धन आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि हर जिले की कृषि और बागवानी क्षमता का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को बहु-फसली, बहु-उत्पाद और उच्च मूल्य आधारित खेती से जोड़कर स्थायी आय के अवसर प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 1,40,000 एकड़ सेम एवं लवणीय भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जैव निकास के तहत सफेदा (यूकेलिप्टस) के पेड़ किसानों के खेतों की मेड़ों, नहरों के किनारों तथा नालों की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर लगाए जाएं, ताकि जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक रूप से कम किया जा सके। सफेदा के पेड़ अपनी गहरी जड़ों और अधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण सेम प्रभावित भूमि के सुधार में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र बढ़खालसा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर चिन्हित किए जाएं। इन क्लस्टरों में किसानों को जीवामृत, जैविक घोल, ड्रम और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत द्वारा अपनाई जा रही प्राकृतिक खेती पद्धति को आधार बनाकर इसे लागू किया जाए।

नई संकर किस्में और अनुसंधान को बढ़ावा

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नरमा, सरसों, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलों की नई संकर एवं अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की जाएं। साथ ही ऐसे बीजों और पौधों के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो ओलावृष्टि, जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को सहन कर सकें। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर उपलब्ध भूमि को अनुसंधान एवं परीक्षण के लिए चिन्हित किया जाए, ताकि नई किस्मों और तकनीकों का स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण कर किसानों तक तेजी से पहुंचाया जा सके। विद्यार्थियों और शोध संस्थानों को भी इस अभियान से जोड़कर नवाचार को गति देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में विकसित सफल संकर किस्मों, फल पौधों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाए, ताकि प्रदेश के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली पौध और बीज उपलब्ध हो सकें।

एक नजर

विभाग में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

हिसार. गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (गुजविप्रौवि) के नर्सिंग विभाग में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों में नर्सिंग पेशे के प्रति सेवा भाव, अनुशासन, नैतिकता एवं व्यावसायिक जिम्मेदारियों की भावना का विकास करना था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने अपने संदेश में कहा कि नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाओं का दिल होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी आगे की यात्रा में नैतिकता, करुणा और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने नर्सिंग विभाग व प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी। कुलसचिव डा. विजय कुमार ने अपने संदेश में कहा कि वर्तमान तकनीकी युग में मशीनें भले ही मदद कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी इंसान की सहानुभूति की जगह नहीं ले सकतीं। नर्सिंग स्टाफ विज्ञान और मानवता के बीच एक सेतु होता हैं। उन्होंने आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रवलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मकता एवं ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीन, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रो. सुमित्रा सिंह ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को करुणा, धैर्य एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा निरंतर ज्ञान और कौशल को विकसित करने की प्रेरणा दी। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य श्रीमती संतोष हुड्डा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को नर्सिंग पेशे की गरिमा बनाए रखने, मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने तथा अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ समर्पित रहने का संदेश दिया। स्वागत संबोधन डा. शिखा पहुजा ने किया। धन्यवाद सम्बोधन व मंच संचालन प्रियंका ने किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नर्सिंग शपथ लेते हुए यह संकल्प लिया कि वे मरीजों की सेवा को सर्वोपरि रखेंगे, गोपनीयता बनाए रखेंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तथा अपने पेशे के उच्च आदर्शों के अनुरूप कार्य करेंगे।

सिरसा के डा. अनिल धानुका दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल मोटिवेशन अवॉर्ड 2026 में शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित

सिरसा. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल मोटिवेशन अवॉर्ड 2026 समारोह में शिक्षाविद् डॉ. अनिल धानुका को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।यह भव्य समारोह देशभर से आए फिल्म, संगीत, नृत्य, लेखन एवं अन्य कला क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों, सह-कलाकारों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहाँ अनेक प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।अपने संबोधन में डॉ. धानुका ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए रोजगारयोग्यता के साथ शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कलाकारों को उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष बल दिया, ताकि वे अपने क्षेत्र में और अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकें।उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ऑनलाइन एवं डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। और कलाकारों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर डॉ. अनिल धानुका एवं संगीत विशेषज्ञ देबोजीत लाहिरी ने डॉ. संजय जोहरी की पुस्तकों दि इनविजिबल कन्फ्लिक्ट्स एवं किन्नर माँ का विमोचन किया।साथ ही डॉ. धानुका ने डॉ. आलोक कुमार भार्गव की पुस्तक त्रयीवाणी का भी विमोचन किया तथा अतिथियों को अपनी हस्ताक्षरित पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।इसके अतिरिक्त नेपाल की प्रसिद्ध लोक कवियित्री नीलिमा मास्के श्रेष्ठ की नेपाली काव्य रचना रंग जीवन को का भी विमोचन किया गया।यह सम्मान न केवल डॉ. अनिल धानुका के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी उजागर करता है।

हनुमान ढाणी चौक सर्कुलर मार्ग पर एक माह से बह रहा है पेयजल : भारद्वाज

भिवानी. विश्व जल दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति एवं सदाचारी शिक्षा समिति द्वारा शहर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जल साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लीकेज पाइपलाइन, व्यर्थ बहते पानी और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित विभाग व उपभोक्ताओं को जल संरक्षण साक्षरता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। आज स्थानीय हनुमान ढाणी चौक सर्कुलर मार्ग पर हजारों लीटर पेयजल पाईप लाईन से व्यर्थ बह रहा है। उसके लिए संबंधित विभाग व उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया । अभियान के सूत्रधार एवं भारत सरकार से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि पानी की हर बूंद अनमोल है, इसे व्यर्थ बहने से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऐसे में यदि अभी से पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में पेयजल की गंभीर किल्लत हो सकती है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइनों में हो रहे लीकेज पर चिंता जताते हुए कहा कि संबंधित विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां भी पाइपलाइन टूटी हुई है या गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य किया जाना चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और लोगों तक स्वच्छ जल पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हनुमान ढाणी चौक सर्कुलर मार्ग पर एक माह से हजारों लीटर पेयजल खराब हो रहा, विभाग इस मामले जल्द संज्ञान लेते हुए पेयजल को व्यर्थ होने से बचाएं। अशोक भारद्वाज ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जितनी आवश्यकता हो, उतना ही पानी उपयोग में लें और जल का सदुपयोग करें। उन्होंने सुझाव दिया कि घरों और गलियों में लगे नलों पर टोटी अवश्य लगाई जाए, जिससे पानी का अनावश्यक बहाव रोका जा सके।

भंडारा सामग्री लेकर श्री बजरंग भंडारा सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी रवाना

सिरसा। श्री बजरंग भंडारा सेवा ट्रस्ट रजि. 9388 सिरसा द्वारा सालासर धाम (राज.) में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक लगाए जाने वाले 24वें अर्द्धवार्षिक विशाल भंडारे के लिए सिरसा से ट्रस्ट पदाधिकारी भंडारा सामग्री लेकर रवाना हुए। ट्रस्ट के प्रधान शिव शंकर गोयल ने बताया कि श्याम प्रेमी वरूण वधवा ने झंडी देकर भंडारा सामग्री दल को अनाज मंडी से श्रीबालाजी महाराज का जयकारा लगाकर रवाना किया। प्रधान शिव शंकर गोयल ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी तीन दिवसीय भंडारा लगाया जा रहा है। भंडारे में तीन दिन लगातार लंगर-भंडारा होगा, वहीं श्रद्धालुओं के लिए फ्रूट की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

गेहूं खरीद तैयारियों का एसडीएम ने लिया जायजा

टोहाना. उपमंडलाधीश आकाश शर्मा ने बुधवार को अनाज मंडी टोहाना, अतिरिक्त अनाज मंडी टोहाना, खरीद केंद्र नागला व ठरवा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद की तैयारियों और किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। एसडीएम ने मंडी और खरीद केंद्र में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसानों की सुविधा सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने खरीद का कार्य पूरी पारदर्शिता और सुचारू तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, एसडीएम ने अनाज भंडारण की व्यवस्था, वेट मशीनों के संचालन और खरीद से संबंधित बारीकियों की जांच की। एसडीएम ने कहा कि मंडियों में बेहतर साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाएं बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। गेट पास, सीसीटीवी, और बायोमेट्रिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को शौचालयों की नियमित सफाई, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की निरंतर जांच और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनाज मंडियों की अटल किसान कैंटीनों में मिलेगा अच्छी गुणवत्ता का भोजन : विश्राम मीणा

पंचकूला ऑब्जर्वर

कुरुक्षेत्र. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला की अनाज मंडियां की अटल किसान कैंटीनों पर अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। कैंटीनों में भोजन बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए डीएफएससी को गैस उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उठान कार्य में शामिल होने वाले वाहनों की जीपीएस के माध्यम से ट्रेकिंग की जाएगी। सभी अनाज मंडियों में समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारी के नेतृत्व में टीम तैनात रहेगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा बुधवार को थानेसर अनाज मंडी की अटल किसान कैंटीन व अनाज मंडी का निरीक्षण कर रहे थे। इसके उपरांत उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मार्केट कमेटी कार्यालय में खरीद एजेंसियों, उठान एजेंसी, अधिकारियों, आढ़तियों, व्यापारियों के साथ बैठक में समस्याओं पर चर्चा भी की। उन्होंने अनाज मंडी स्तर पर एक-एक टीम को समाधान के लिए नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इस बार सरकार ने खरीद कार्य में नवाचार को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में किसान अपने मोबाइल में एप के माध्यम से गेटपास बना सकेगा। गेटपास बनाने के बाद किसानों को अपनी बायोमेट्रिक करवानी होगी। अनाज मंडी में लगाए गए बायोमेट्रिक यंत्र से डाटा आगे बढने् के बाद ही ई-खरीद केंद्र पर किसानों की फसल का डाटा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसानों को आढ़ती, व्यापारी और अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए और किसानों की सहायता के लिए अधिकारी कर्मचारी की टीम मौजूद रहेगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अनाज मंडियों में शौचालयों, साफ-सफाई, बायोमेट्रिक और उठाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने लिफ्टिंग को लेकर इस बार दिक्कत ना हो, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयार की है। बैठक के दौरान आढ़तियों, व्यापारियों व अधिकारियों से सीजन में आने वाली समस्याओं को जानकर उनके समाधान की योजना भी तैयार की जा रही है। इस बारे लिफ्टिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की सभी प्रकार की तैयारियों व टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।

विद्यार्थियों का मंगल तिलक और मुंह मीठा करवाकर मनाया प्रवेश उत्सव

निसिंग. एक अप्रैल से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले शुरू हो गए। स्कूल प्रशासन ने विधार्थियो का प्रथम प्रवेश अपने अपने तरीके से मनाया। जिसमे शिक्षकों ने विद्यार्थीयो का स्कूल में प्रथम प्रवेश पर स्वागत किया। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोंदर में स्टेट अवॉर्डी हिंदी शिक्षक विनोद कुमार ने विभिन्न कक्षाओं के प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं भविष्य में और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। कम प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को मेधावी छात्राओं से सीख लेने की सलाह दी। इस दौरान स्कूल में प्रथम प्रवेश पाने वाली छठी व नौवीं कक्षा की छात्राओं का स्टाफ सदस्यों सहित मंगल तिलक और फूल मालाए पहनकर स्वागत किया । छात्राओं का मुंह मीठा भी करवाया गया। क्षेत्र के अन्य स्कूलों में भी विद्यार्थियों का प्रथम प्रवेश पर स्वागत कर एडमिशन किया गया। जिनमे मंजूरा, अगोंध, कत्तलेहड़ी, हथलाना, निसिंग, ब्रास, बालू, पिंगली, जुंडला, गुल्लरपुर व प्योंत सहित अन्य गांवो के स्कूल शामिल है।

नव-प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

हिसार. लाला लाजपत राय पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार के पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 बैच के 61 नव-प्रशिक्षित स्नातक विद्यार्थियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राएं और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशु चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. मनोज रोज ने की, जबकि केरस कंपनी के जीएम डॉ. दीपक कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके उपरांत डॉ. ज्ञान सिंह द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने नव-प्रशिक्षित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके पश्चात अधिष्ठाता डॉ. मनोज रोज ने नव-प्रशिक्षित स्नातकों को शपथ दिलाई तथा इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कुलपति प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार वर्मा का बधाई संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अपने संदेश में उन्होंने नव-प्रशिक्षित स्नातकों, उनके अभिभावकों एवं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पशु-चिकित्सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को केवल रोजगार तक सीमित न रहकर डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चिकित्सा जांच प्रयोगशालाओं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित पशु उत्पाद विपणन जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विद्यार्थी एक सक्षम पशु-चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अधिष्ठाता डॉ. मनोज रोज ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत एवं जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर सीखना और समय के अनुसार स्वयं को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पशु चिकित्सकों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां गरीब एवं छोटे किसानों की आजीविका काफी हद तक पशुधन पर निर्भर करती है। ऐसे में पशु चिकित्सकों का दायित्व केवल उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों को सही मार्गदर्शन देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का भी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने अध्ययन काल में अर्जित वैज्ञानिक ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल का उपयोग समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, विशेषकर गरीब पशुपालकों की सेवा के लिए करें तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में पशु चिकित्सा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं—विद्यार्थी सरकारी सेवाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र (प्राइवेट जॉब) में भी उत्कृष्ट करियर बना सकते हैं, वहीं स्वरोजगार के माध्यम से क्लिनिक, डेयरी, पशु फार्म या अन्य उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। डॉ. रोज ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की इस उपलब्धि में उनके माता-पिता का त्याग, सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सभी अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि आज का यह दिन उनके लिए गर्व का क्षण है।

विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए केरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जीएम डॉ. दीपक कुमार ने अपनी प्रयोगशाला की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को आधुनिक पशु चिकित्सा जांच तकनीकों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर केरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020 बैच के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन विद्यार्थियों को उनके क्लिनिकल विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई। इनमें तरुण (147.75 अंक), रिद्म (147.30 अंक) एवं ऋषभ (147.25 अंक) को मेरिट के आधार पर सम्मानित किया गया।

फसल खरीद में नए नियम बने किसानों के लिए परेशानी का सबब: रामचंद्र गुर्जर

कैथल. कांग्रेस कमेटी कैथल जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड ने आरोप लगाया कि रबी सीजन के दौरान गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर सरकार द्वारा लागू की जा रही नई प्रक्रियाएं और नियम किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला किसानों की आवाज व मांगों को लेकर सडक् से लेकर संसद तक बुलंद कर रहे है। किसानों के हितों पर सुरजेवाला कोई आंच नहीं आने देंगे। यदि सरकार ने जल्द ही इन प्रक्रियागत बाधाओं को दूर नहीं किया, तो किसान और खेत मजदूर सडकों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। नई अनाज मंडी ढांड स्थित कांग्रेस कार्यालय में बातचीत करते हुए उन्होंने इसे किसान विरोधी फरमान बताते हुए कहा कि ऐसे हथकंड़ों के माध्यम से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद को जानबूझकर प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेसी नेता रामचंद्र गुर्जर ने कहा कि गेहूं और सरसों की खरीद में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार खरीद प्रक्रिया को जटिल बनाकर खरीद लक्ष्य घटाने, उठान रोकने और स्टोरेज व्यवस्था कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेता रामचंद्र गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें पहले वापस लिए गए कृषि कानूनों के बाद अब पिछले दरवाजे से एमएसपी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी हो चुकी है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार किसान हित में कदम उठाते हुए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, एमएसपी पर फसलों की गारंटी सुनिश्चित की जाए, मंडियों में सुचारु उठान और भंडारण व्यवस्था की जाए और निर्धारित समय पर फसलों का भुगतान किया जाए।

शिव महापुराण कथा सुनना अत्यंत सुखदायी और कल्याणकारी : कथा व्यास पंडित कृष्ण शरण शास्त्री

भारत माता मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा में विभिन्न क्षेत्रों से उमड़े श्रद्धालु

पंचकूला ऑब्जर्वर

हिसार. समाजसेवी स्व. चौ. फतेहचंद, स्व. माता हरबंस कौर एवं स्व. विजय शर्मा की स्मृति में भारत माता मंदिर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ?र हिस्सा लिया। वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित कृष्ण शरण शास्त्री महाराज ने श्री शिव महापुराण कथा का महत्व समझाते हुए कहा कि यह कथा सुनना अत्यंत सुखदायी और कल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण कथा बहुआयामी है

और यह मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीना सिखाती है। एम. सी. कॉलोनी स्थित भारत माता मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित कृष्ण शरण शास्त्री ने समझाया कि जिस इंसान पर परमात्मा की कृपा होती है, उसे ही श्री रामकथा, श्रीमद भागवत कथा या श्री शिव महापुराण कथा सहित अन्य धार्मिक कथाएं सुनने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि चाहे इंसान कितनी कोशिश कर ले या कितना ही मन बना ले लेकिन परम पिता परमात्मा की अनुकंपा के बिना उसे कथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिलता। पंडित कृष्ण शरण शास्त्री ने कहा कि यह हिसारवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें भारत माता मंदिर के प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर मिला है। श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन भारत माता मंदिर में लता सिंगल, मनोरमा गुप्ता, प्रवीन अरोड़ा, सुनीता रहेजा, सुनीता शर्मा, मधु बंसल, उषा ठकराल, बिमला कथूरिया, अनिता चौधरी, इंदु गोयल व कमलेश गोयल विशेष रूप से उपस्थित रही। इनके साथ ही भारत माता मंदिर के संरक्षक अनिल महत्ता, पुजारी पंडित रामकिशोर शुक्ल, आचार्य संतोष शास्त्री, गोविन्द मधु, विवेक पाठक, सुभाष यादव व अशोक सिंधवानी सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। संरक्षक अनिल महत्ता ने बताया कि एम. सी. कॉलोनी स्थित भारत माता मंदिर में सायं 4 बजे से सायं 7 बजे तक वृंदावन के प्रसिद्ध कथा व्यास पंडित कृष्ण शरण शास्त्री 4 अप्रैल तक श्री शिव महापुराण कथा करेंगे। 5 अप्रैल को प्रात- हवन के उपरांत प्रात- 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत माता मंदिर अध्यात्म के साथ देशभक्ति की भी अलख जगा रहा है। इसलिए यहां देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के साथ ही भारत माता की ओजस्वी प्रतिमा स्थापित की गई है।

उन्होंने बताया कि भारत माता मंदिर परिसर में गंगा माता, गऊ माता के साथ-साथ दुर्गा माता, श्याम बाबा, राधा-कृष्ण, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, पंचमुखी हनुमान व सिद्धिविनायक गणेश के विग्रह की स्थापना की गई है।

पाचन से लेकर दिल तक का रखें ख्याल, अंजीर में छिपे हैं कई चमत्कारी गुण

आजकल लोग बेहतर स्वास्थ्य की चाह में विदेशी और महंगे फलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इस होड़ में वे अपने आसपास उपलब्ध पारंपरिक फलों के गुणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अंजीर एक ऐसा ही फल है, जिसे सदियों से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि अंजीर में प्रचुर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को ब?ाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, अंजीर को मधुर और शीतल गुणों वाला फल माना जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह खासतौर पर पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। विज्ञान की मानें तो, अंजीर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। यही फाइबर आंतों को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है। जब पाचन सही रहता है, तो शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है, जिससे सेहत में सुधार आता है। अंजीर हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को बोन डेंसिटी की समस्या होती है, उनके लिए अंजीर का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है।

एनर्जी के लिए भी अंजीर एक अच्छा विकल्प है। इसमें प्राकृतिक शुगर और आयरन पाया जाता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाता है, जिससे थकान कम होती है और व्यक्ति दिनभर सक्रिय महसूस करता है। यही कारण है कि जिन लोगों को कमजोरी या एनीमिया की समस्या होती है, उन्हें सीमित मात्रा में अंजीर लेने की सलाह दी जाती है।

दिल की सेहत के लिए भी अंजीर को लाभकारी माना जाता है। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की अछी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। पोटेशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटता है। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम होता है। नियमित और संतुलित मात्रा में अंजीर का सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।

सिद्धांत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव पर की बात

सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने छोटे से करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। यही कारण है कि उनकी गिनती इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारों में होती है। असल जिंदगी में काफी ग्राउंडेड नजर आने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने अब सोशल मीडिया पर फैशन के बढ़ते दबाव के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने अपने लक्ष्य को लेकर भी बताया।

मेरी फिल्मों में ही होती है फैशन

बातचीत में सिद्धांत चतुर्वेदी स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरी पहली पहचान एक अभिनेता के रूप में है, न कि फैशन आइकन के रूप में। एक्टर ने कहा कि मैं एक अभिनेता बनने आया हूं, मुझे वह अवसर मिला और आज मैं एक अभिनेता हूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फैशन की बात करें तो, यह सब मेरी फिल्मों में ही है, मतलब वे हमें अच्छे कपड़े पहनाते हैं। मेरा मानना है कि सबका अपना-अपना फैशन होता है। मुझे साधारण रहना ज्यादा पसंद है। फैशन को किसी पर थोपना नहीं चाहिए।

बेफिक्र इंसान होता है सबसे ज्यादा फैशनेबल

फैशन को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए सिद्धांत ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे फैशनेबल व्यक्ति वह है, जो ज्यादा नहीं सोचता, थोड़ा बेफिक्र और बिंदास होता है। आखिरकार किसी के व्यक्तित्व को देखकर उसका स्वैग अपने आप झलक जाता है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, तो आप दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है।

इस बायोपिक में नजर आएंगे सिद्धांत

सिद्धांत चतुर्वेदी के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता आखिरी बार इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'दो दीवाने सहर में' में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर प्रमुख भूमिका में थीं। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया ही हासिल हुई थी। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। उनकी आगामी फिल्मों में 'वी. शांताराम' शामिल है। यह दिग्गज फिल्ममेकर वी. शांताराम की बायोपिक है। इसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी।

आरती छाबड़िया ने बॉलीवुड की राजनीति पर किए खुलासे

अभिनेत्री आरती छाबड़िया काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं। उनकी आखिरी प्रमुख भूमिका 2010 में आई फिल्म 'मिलेंगे मिलेंगे' में थी। अब वह बॉलीवुड में वापसी करने की तैयारी में हैं। हालांकि, आरती का ऐसा कहना है कि वो अपने करियर में कई बार बॉलीवुड में होने वाली राजनीति का शिकार हुई हैं। जिसके चलते कभी उनका रोल कट गया, तो कभी उनका पूरा गाना ही फिल्म से हटा दिया गया।

इंडस्ट्री में होती है काफी पॉलिटिक्स

अल्फाटॉक के साथ एक हालिया पॉडकास्ट में आरती छाबड़िया ने इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के कारण अपने पेशेवर जीवन में आई बाधाओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 'पार्टनर', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'मिलेंगे मिलेंगे' और अन्य फिल्मों में उनके कई सीन काट दिए गए थे। इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि कई बार मेरे रोल काट दिए गए या कम कर दिए गए। टाइटल रोल निभाने के बावजूद, ऐसा लगता था जैसे मैं फिल्म में दिख ही नहीं रही। कई फिल्में ऐसी थीं, जिनमें मेरे सीन काट दिए गए और गाने शूट होने के बाद हटा दिए गए। 'मिलेंगे मिलेंगे' में शाहिद कपूर के साथ मेरा पूरा गाना था, लेकिन उसे काट दिया गया। बोनी उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। आपको पता नहीं होता कि ये फैसले क्यों लिए जाते हैं। हम कलाकार हमेशा प्रोड्यूसर के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें कोई पछतावा नहीं है।

कई फिल्मों में काटे गए मेरे रोल्स

अभिनेत्री ने आगे कहा कि सिर्फ एक ही फिल्म में नहीं, बल्कि कई फिल्मों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ऐसी कई फिल्में थीं, जिनमें अलग-अलग कारणों से मेरे रोल काट दिए गए थे। जैसे कि सलमान खान और गोविंदा की 'पार्टनर' में मेरी भूमिका वैसी नहीं थी जैसी तय की गई थी। यह एक कैमियो रोल था, लेकिन फाइनल कट में शामिल किए गए रोल से बड़ा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म हिट रही। मुझे कोई अफसोस नहीं है। 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'आवारा पागल दीवाना' में भी ऐसा ही हुआ। मायने सिर्फ इतना रखता है कि फिल्म ने आखिर में अच्छा प्रदर्शन किया।

'धुरंधर' और 'रामायण' के बाद क्या एसएस राजामौली की 'वाराणसी' दो भागों में होगी रिलीज?

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद अब फैंस फिल्म 'रामायण' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म है, जिसकी रिलीज पर फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। वह फिल्म राजामौली की 'वाराणसी' है। जानिए क्या 'धुरंधर' और 'रामायण' की तरह ही 'वाराणसी' भी दो भागों में बनेगी?

क्या दो भागों में रिलीज होगी 'वाराणसी'?

पहले राजामौली ने 'वाराणसी' को दो भागों में बनाने की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की एक खबर के अनुसार, फिल्म 'वाराणसी' दो भागों में रिलीज हो सकती है। दरअसल, फिल्म की कहानी इतनी लंबी है कि तीन घंटे से ज्यादा समय में भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे दो भागों में बनाने का विचार किया जा रहा है। 'धुरंधर' की तरह 'वाराणसी' भी दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म समय यात्रा पर आधारित है। इसका बजट 1300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यह भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलज होगी।

'धुरंधर'– 'रामायण' और अब 'वाराणसी'

'धुरंधर 2' अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है। वहीं राजामौली की आगामी 'रामायण' फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है। वहीं अब 'वाराणसी' आखिरकार दो भागों में रिलीज होगी या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

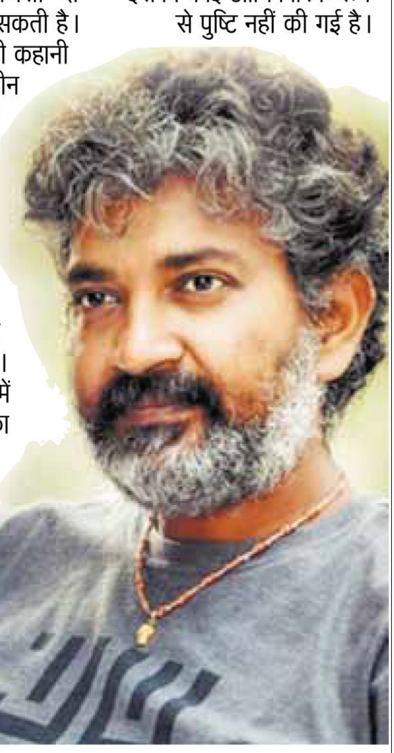

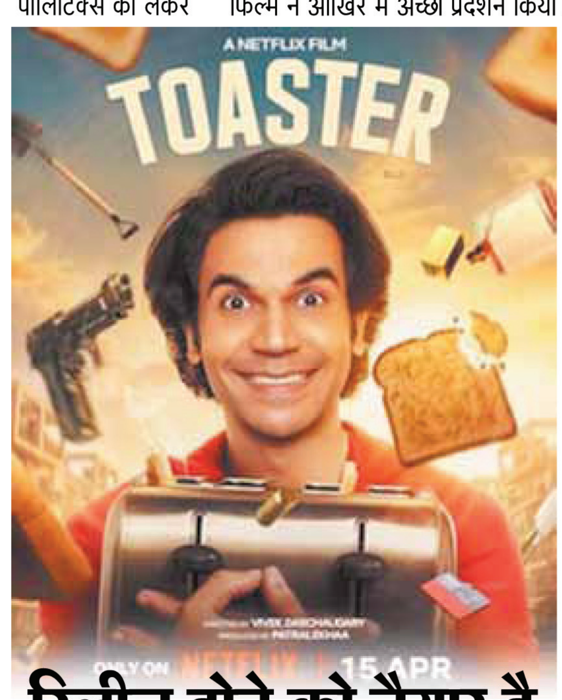

रिलीज होने को तैयार है राजकुमार राव-सान्या की फिल्म 'टोस्टर'

अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले राजकुमार राव अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'टोस्टर' और इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। राजकुमार राव की यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी और इसके अनाउंसमेंट के लिए राजकुमार राव ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। मालूम हो कि 'टोस्टर' को राजकुमार की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है। 'टोस्टर' का ऐलान साल 2025 में किया गया था, और अब यह फाइनली रिलीज होने को तैयार है। 'टोस्टर' 15 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसमें राजकुमार राव के अलावा सान्या मल्होत्रा, फराह खान, अर्चना पूरन सिंह, अभिषेक बनर्जी और सीमा पहवा जैसे एक्टर्स हैं। यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे विवेक दास चौधरी ने डायरेक्ट किया है।

मनोज बाजपेयी ने पर्सनैलिटी राइट्स जैसे मुद्दों पर अपनी राय दी

दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल होने पहुंचे। इस बीच मनोज बाजपेयी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स जैसे मुद्दों पर अपनी राय दी। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज बाजपेयी ने साफ कहा कि अगर कोई उनके काम या उनसे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए उन्हें पैसे मिलने चाहिए। उनका कहना था कि एक कलाकार अपनी पहचान और भरोसा वर्षों की मेहनत से बनाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल बिना अनुमति या बिना भुगतान के नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर हमारी चीज कोई यूज करेगा, तो उसके पैसे हमें मिलने चाहिए। मैं 32 साल से काम कर रहा हूं, और इस दौरान जो पहचान बनाई है, उसका अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो उसे उसके अधिकार के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।' इस दौरान मनोज बाजपेयी ने ये भी बताया कि वो फेस्टिवल में एक खास 'इन-कन्वर्सेशन' सेशन का हिस्सा बनने वाले हैं, जहां वो अपने लंबे फिल्मी सफर के बारे में बात करेंगे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी : श्री शिवम ग्रोवर, मुद्रक : इंप्रेशन प्रिंटिंग प्रेस एंड पैकेजिंग लिमिटेड, भूतल प्लांट नं.-22, प्रथम तल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पंचकूला में मुद्रित। प्रकाशन स्थल : पंचकूला ऑब्जर्वर, प्लॉट नं.-365, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, पंचकूला। मुख्य संपादक : श्री अरुण ग्रोवर, समाचार चयन एवं प्रकाशन की समस्त जिम्मेदारी प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (PRP) एक्ट के अंतर्गत पंचकूला न्यायालय क्षेत्राधिकार में निहित होगी। RNI पंजीकरण संख्या : HRB/L/25/A3417 संपर्क मोबाइल : 98888-86909, ई-मेल : panchkulaobservernews@gmail.com